



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 339]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 06 सितम्बर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30.— बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,—
 - (i) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, शब्दों और चिह्नों “प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट),” के पश्चात् तथा शब्दों “पारस्परिक निधि द्वारा निर्गमित” से पूर्व, निम्नलिखित शब्द और चिह्न अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

“प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटीज़ रीसीट्स),”

- (ii) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (फ) में, शब्द, चिह्न और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008” निम्नलिखित शब्दों, चिह्नों और अंक से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, —
- “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008”
- (iii) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यछ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, —
- “(यछ) “प्रतिभूत ऋण लिखतों” (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 के अधीन इसके लिए नियत है;”
- (iv) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यछ) के पश्चात् तथा खंड (यज) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —
- “(यछक) “प्रतिभूत रसीदों” (सिक्यूरिटीज़ रिसीट्स) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 के अधीन इसके लिए नियत है;”
- (v) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यज) में, शब्द, चिह्न और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008” निम्नलिखित शब्दों, चिह्नों और अंक से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, —
- “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008”
- (vi) विनियम 3 में, खंड (घ) के पश्चात् तथा खंड (ङ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —
- “(घक) प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटी रिसीट्स);”
- (vii) विनियम 81 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008” निम्नलिखित शब्दों, चिह्नों और अंक से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, —
- “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008”
- (viii) अध्याय-VIII के पश्चात् और अध्याय-IX से पूर्व, निम्नलिखित नया अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

“अध्याय-VIII क

उस सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) को सूचीबद्ध कराया हो

लागू होना

87क. (1) इस अध्याय के प्रावधान प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) के उस निर्गमकर्ता (इश्युअर) पर लागू होंगे जिसने अपनी प्रतिभूति रसीदों को सूचीबद्ध कराया हो, और निर्गमकर्ता (इश्युअर) तथा उसका प्रायोजक (स्पॉन्सर) इन विनियमों के प्रत्येक प्रावधान का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) पदों “आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी)”, “निवेशक” (विनिधानकर्ता), “निर्गम” (इश्यू), “निर्गमकर्ता” (इश्युअर), “विक्रय के लिए प्रस्ताव” (ऑफर फॉर सेल), “निजी स्थानन प्रस्ताव” (प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर), “अर्हित क्रेता” (क्वालिफाइड बायर), “स्कीम”, “प्रतिभूति रसीदों” (सिक्यूरिटी रिसीट्स), “प्रायोजक” (स्पॉन्सर), और “मूल्यांकक” (वैल्यूअर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डेट इन्स्ट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 के अधीन इनके लिए नियत है।

स्टॉक एक्सचेंजों को सूचनाएँ और घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण

87ख. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को समस्त घटनाओं या जानकारी (जिनका उल्लेख अनुसूची-III के भाग-ड में किया गया है) का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), जल्द से जल्द, किंतु घटना के घटित होने या जानकारी मिलने से चौबीस घंटों के भीतर ही, करेगी:

परंतु यह कि यदि घटना के घटित होने या जानकारी मिलने से चौबीस घंटों के बाद प्रकटीकरण किया जाता है, तो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी ऐसे प्रकटीकरणों के साथ-साथ हुई देरी के संबंध में स्पष्टीकरण भी देगी।

(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, इस विनियम में उल्लिखित प्रकटीकरणों के संबंध में, ऐसे प्रकटीकरणों के संबंध में होने वाले बदलावों आदि की जानकारी (अपडेट) [स्पष्टीकरणों के साथ] नियमित आधार पर तब तक प्रदान करती रहेगी, जब तक घटना का समाधान / समापन न हो जाए।

(3) सूचीबद्ध एंटीटी, किन्हीं घटनाओं या जानकारी के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के सटीक और यथोचित उत्तर देगी:

परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंज जल्द से जल्द जानकारी तथा स्पष्टीकरण का प्रसार करेगा (करेंगे)।

(4) सूचीबद्ध एंटीटी, स्वप्रेरणा से भी, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचित की गई किसी घटना या जानकारी की पुष्टि कर सकेगी या उससे इनकार कर सकेगी।

(5) सूचीबद्ध एंटीटी अपने वेबसाइट पर या प्रायोजक के वेबसाइट पर ऐसी समस्त घटनाएँ या जानकारी प्रकट करेगी जिन्हें इस विनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट किया जा चुका हो, और ऐसे प्रकटीकरण सूचीबद्ध एंटीटी के वेबसाइट पर कम से कम पाँच वर्षों की अवधि तक डालकर रखे जाएँगे और उसके बाद सूचीबद्ध एंटीटी की अभिलेखों संबंधी (आर्काइवल) नीति (जो उसके वेबसाइट पर प्रकट की गई हो) के अनुसार डालकर रखे जाएँगे।

मूल्यांकन, रेटिंग (साख निर्धारण) और शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का प्रकटीकरण

87ग. (1) जिस निर्गमकर्ता की प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटी रिसीट्स) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) सूचीबद्ध प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर (अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर तक की स्थिति के अनुसार) कराया जाए;
- (ii) मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाए; और
- (iii) शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) ऐसे स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर निकाला जाए और उसकी घोषणा आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा तिमाही की समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कर दी जाए।

(2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) छमाही आधार पर प्रतिभूति रसीदों की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने और उसके बाद शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की मौजूदा अपेक्षा का भी पालन करेगा और/या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली किसी दूसरी अपेक्षा का भी पालन करेगा:

परंतु यह कि वर्ष की उन दोनों तिमाहियों में (जब बाहर से मूल्यांकन करवाना और क्रेडिट रेटिंग करवाना दोनों जरूरी हों), निर्गमकर्ता (इश्युअर) निकाले गए दोनों शुद्ध आस्ति मूल्यों में से उस शुद्ध आस्ति मूल्य को प्रकट करेगा, जो कम हो।

प्रतिभूति रसीदों संबंधी शर्तें आदि

87घ. (1) जारी की गई (निर्गमित / इश्यूड) कोई भी प्रतिभूति रसीद (सिक्यूरिटी रिसीट) केवल वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002) के अनुसार अर्हित क्रेताओं (क्वालिफाइड बायर) के पक्ष में ही अंतरणीय (ट्रांसफरेबल) होगी।

(2) जब तक कि निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि में कुछ और उल्लेख न हो, तब तक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी अपनी किन्हीं सूचीबद्ध प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का चयन भुगतान के लिए, आनुपातिक आधार पर या लॉट पर करने के सिवाय, नहीं करेगी और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को उसके ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत करेगी।

रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट)

87ड. (1) सूचीबद्ध एंटीटी प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) के धारकों (होल्डर्स) को भुगतान करने के लिए या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे अन्य प्रयोजनों (उद्देश्यों) से एक रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) तय करेगी।

(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, रिकॉर्ड तिथि का प्रयोजन (उद्देश्य) निर्धारित करते हुए, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) की सूचना (नोटिस) कम से कम सात कार्य-दिवस (सूचना देने की तारीख और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले देगी अथवा उतने दिनों पहले देगी जितने दिनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज सहमत हो (हों) या जितने की अपेक्षा करे (करें)।”

(ix) अनुसूची-III में, भाग-घ के पश्चात् और अनुसूची-IV से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

“भाग-ड: स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र): प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटी रिसीट्स)

[विनियम 87ख (1) देखें]

क. निम्नलिखित घटनाओं / जानकारी के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), महत्ता संबंधी दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) पर विचार किए बिना, जल्द से जल्द, किंतु घटना के घटित होने या जानकारी मिलने से चौबीस घंटों के भीतर ही किया जाएगा:

- (1) नियत तारीख या पहले ही से तय की गई तारीख, यदि कोई हो, से नकदी प्रवाहों (कैश फ्लो) में हुई किसी देरी या हो सकने वाली किसी देरी के संबंध में;
- (2) प्रकट किए गए नकदी प्रवाहों के मूल्य में किसी बदलाव, यदि कोई हो, के संबंध में;
- (3) आए किसी नकदी प्रवाह या आ सकने वाले किसी नकदी प्रवाह के संबंध में (इस प्रकार आए नकदी प्रवाह की रकम सहित);
- (4) क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट) के लिए उठाए गए कदमों में किसी बदलाव के संबंध में;
- (5) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से समय-समय पर ली जाने वाली रेटिंग अथवा रेटिंग में हुए किसी बदलाव या हो सकने वाले किसी बदलाव के संबंध में;
- (6) समय-समय पर शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के संबंध में;
- (7) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी या मूल्यांकक (वैल्यूअर) में बदलाव किए जाने के किसी प्रस्ताव या किसी बदलाव के संबंध में;
- (8) आस्तियों (असेट्स) के प्रोफाइल में किसी बदलाव [फिर चाहे वह बदलाव नई आस्ति आने (एक्रीशन) की वजह से हुआ हो या मौजूदा पूल से आस्तियों की वसूली होने की वजह से हुआ हो] के संबंध में;
- (9) आस्तियों (असेट्स) के अर्जन (एक्विज़िशन) के किसी प्रस्ताव (जिसमें अर्जन संबंधी शर्तें आदि शामिल हैं) के संबंध में;
- (10) वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट्स) की वसूली न हो सकने या वसूली न होने के संबंध में और उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों के संबंध में;
- (11) अंडरलाइंग आस्तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) के स्वरूप में किसी बदलाव के संबंध में;

- (12) प्रतिभूति रसीदों (सिक्क्यूरिटी रिसीट्स) संबंधी शर्तों आदि (जिसमें अधिकार या विशेषाधिकार या स्वरूप आदि शामिल हैं) में किसी बदलाव होने या बदलाव किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में;
- (13) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा कॉल / पुट ऑप्शन [मोचन (रिडीम) करने का अधिकार] या ऐसे ही किसी ऑप्शन का प्रयोग करने की बाबत किसी प्रस्ताव के संबंध में या प्रयोग किए जाने के संबंध में;
- (14) प्रतिभूति रसीदों (सिक्क्यूरिटी रिसीट्स) संबंधी शर्तों आदि के तहत किसी प्रसंविदा (कोविनेन्ट) के किसी उल्लंघन के संबंध में;
- (15) जिस नकदी प्रवाह के संबंध में दावा न किया गया हो, उसे जब्त करने (उसके समपहरण) या किन्हीं प्रतिभूति रसीदों को जब्त करने के किसी प्रस्ताव के संबंध में या इस प्रकार की गई किसी जब्ती के संबंध में;
- (16) समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) में किसी बदलाव के संबंध में;
- (17) दूसरे बैंकों के अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग) ऋणों में प्रतिशत के रूप में होल्टिंग में किसी बदलाव के संबंध में;
- (18) सूचीबद्ध एंटीटी के कारोबार (कारबार) / क्रियाकलापों के सामान्य स्वरूप आदि में किसी बदलाव के संबंध में, किसी प्राकृतिक आपदा आदि के कारण कामकाज में खलल पड़ने के संबंध में;
- (19) किन्हीं कुर्की या प्रतिपेक्षात्मक आदेशों (प्रोहिबिटरी ऑर्डर) के संबंध में, जिनके माध्यम से सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी को प्रतिभूति रसीदें (सिक्क्यूरिटी रिसीट्स) अंतरित (ट्रांसफर) किए जाने से रोका जाता हो;
- (20) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल) के पास किन्हीं अंडरलाइंग आस्तियों (असेट्स) की बाबत कोई मामला शुरू होने या उस मामले की अद्यतन स्थिति के संबंध में;
- (21) अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) की जिस बैठक में प्रतिभूति रसीदें जारी (निर्गमित / इश्यू) करने अथवा प्रतिभूति रसीदों के धारकों (होल्डर्स) के अधिकारों या हितों को प्रभावित करने वाली किसी अन्य बात को लेकर सिफारिश करने या घोषणा करने के बारे में विचार किए जाने का प्रस्ताव हो, उस बैठक की अग्रिम सूचना और साथ ही ऐसी बैठकों के नतीजे के संबंध में;
- (22) प्रायोजक (स्पॉन्सर) या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों / की मैनेजेरियल पर्सनेल) द्वारा की गई धोखाधड़ी (कपट) या चूकों (डिफॉल्ट) के संबंध में अथवा प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या प्रायोजक की गिरफ्तारी के संबंध में;
- (23) निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों [प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर), कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) आदि], लेखापरीक्षक (ऑडिटर) और प्रायोजक के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) में बदलाव के संबंध में;
- (24) उपरोक्त के अलावा, सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को ऐसी समस्त जानकारी प्रकट (ऐसे समस्त प्रकटीकरण / डिस्क्लोज़र) करेगी जो उसे मौजूदा अपेक्षा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रकट करनी जरूरी हो और/या कोई दूसरी जानकारी प्रकट करेगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए;
- (25) यदि कोई ऐसी घटना घटित होती हो या सूचीबद्ध एंटीटी के पास ऐसी कोई जानकारी आती हो, जिसका उल्लेख इन विनियमों में न किया गया हो, किंतु जो महत्वपूर्ण हो, तो सूचीबद्ध एंटीटी को इस संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण करने होंगे।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/215/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
 - छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
 - ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी. एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
 - झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
 - ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 06th of September, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the

Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, —

- (i) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (h), after the words and symbols “securitised debt instruments,” and before the word “units”, the following words and symbols shall be inserted, namely,—

“security receipts,”

- (ii) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (v), the words and symbols “Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008” shall be substituted with the following words and symbols, namely,—

Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”

- (iii) in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (zg) shall be substituted with the following words and symbols, namely,—

“securitized debt instruments” shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”

- (iv) in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (zg) and before clause (zh) the following clause shall be inserted, namely,—

“(zga) “security receipts” shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”

- (v) in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (zh), the words and symbols “Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008” shall be substituted with the following words and symbols, namely,—

“Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”

- (vi) in regulation 3, after clause (d) and before clause (e), the following clause shall be inserted, namely.-

“(da) security receipts;”

- (vii) in regulation 81, in sub-regulation (2), the words and symbols “Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008” shall be substituted with the following, namely,—

“Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008”

- (viii) after Chapter VIII, and before Chapter IX, the following new Chapter shall be inserted, namely,—

**“CHAPTER VIII A
OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS SECURITY RECEIPTS**

Applicability.

87A. (1) The provisions of this chapter shall apply to the issuer of security receipts which has listed its security receipts and the issuer and its sponsor shall ensure compliance with each of the provisions of these Regulations.

(2) The expressions “asset reconstruction company”, “investor”, “issue”, “issuer”, “offer for sale”, “private placement offer”, “qualified buyer”, “scheme”, “security receipts”, “sponsor”, and “valuer” shall have the same meaning as assigned to them under Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008.

Intimations and Disclosure of events or information to Stock Exchanges.

87B. (1) The listed entity shall first disclose to stock exchange(s) of all events or information, as specified in Part E of Schedule III, as soon as reasonably possible but not later than twenty four hours from occurrence of the event or information:

Provided that in case the disclosure is made after twenty four hours of occurrence of the event or information, the listed entity shall, along with such disclosures provide explanation for the delay.

(2) The listed entity with respect to disclosures referred to in this regulation, shall provide updates related to such disclosures on a regular basis, till such time the event is resolved/closed, with relevant explanations.

(3) The listed entity shall provide specific and adequate reply to all queries raised by stock exchange(s) with respect to any events or information.

Provided that the stock exchange(s) shall disseminate information and clarification as soon as reasonably practicable.

(4) The listed entity, suo moto, may confirm or deny any reported event or information to stock exchange(s).

(5) The listed entity shall disclose on its website or on the website of the sponsor all such events or information which has been disclosed to stock exchange(s) under this regulation, and such disclosures shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the listed entity, as disclosed on its website.

Valuation, Rating and NAV disclosure.

87C. (1) An issuer whose security receipts are listed on a stock exchange shall ensure that:

- (i) the listed security receipts are valued at the end of each quarter i.e. as on March 31, June 30, September 30 and December 31 of every year;
- (ii) valuation is conducted by an independent valuer; and
- (iii) the net asset value is calculated on the basis of such independent valuation and the same is declared by the asset reconstruction company within fifteen days of the end of the quarter.

(2) The issuer shall also comply with the extant Reserve Bank of India requirement of obtaining credit rating of security receipts at half yearly interval and declaration of the net asset value thereafter and/or any other requirement as prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

Provided that in those two quarters in a year, where both external valuation and credit rating are required, issuer shall disclose lower of the two calculated Net Asset Value.

Terms of Security Receipts.

87D. (1) Any security receipt issued would be transferable only in favour of qualified buyers in terms of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

(2) Unless the terms of issue provide otherwise, the listed entity shall not select any of its listed security receipts for payments otherwise than on pro rata basis or by lot and shall promptly submit to the stock exchange(s) the details thereof.

Record Date.

87E. (1) The listed entity shall fix a record date for payment to holders of security receipts or for such other purposes as specified by the stock exchange(s).

(2) The listed entity shall give notice in advance of at least seven working days (excluding the date of intimation and the record date) to the stock exchange(s) of the record date or of as many days as the stock exchange may agree to or require specifying the purpose of the record date.”

(ix) in Schedule III, after PART D, and before Schedule IV, the following shall be inserted, namely, -

**“PART E: DISCLOSURE OF EVENTS OR INFORMATION TO STOCK EXCHANGES:
SECURITY RECEIPTS
[See Regulation 87B (1)]**

A. The following events/information shall be disclosed by the listed entity without any application of guidelines of materiality as soon as reasonably possible but not later than twenty four hours from occurrence of event or information:

- (1) any delay or expected delay in cash flows from the due date or pre- agreed date if any;
- (2) any change in value of cash-flows as disclosed if any;
- (3) any receipt of cash flow or expected cash flow along with quantum so received;
- (4) any change in credit enhancement measures;
- (5) periodic rating obtained from credit rating agency or any revision in the rating or any expected revision in rating;
- (6) periodic Net Asset Value;
- (7) any proposal to change or change of credit rating agency or Valuer;
- (8) any change in profile of the assets by way of accretion to or realisation of assets from the existing pool;
- (9) any proposal for acquisition of assets including terms of acquisition;
- (10) any expected non-realisation or non-realisation of the financial assets and remedial measures proposed to be undertaken;
- (11) any change in nature of charge on the underlying assets.
- (12) any proposal to change or any change in terms of security receipts including rights or privileges or nature or form etc.;
- (13) any proposal or action with respect to exercising call/put option (right to redeem) or any similar option by the listed entity;
- (14) any breach of covenant(s) under the terms of security receipts;
- (15) any proposal or action for forfeiture of unclaimed cash flow or forfeiture of any security receipts;
- (16) any change in resolution plan;

- (17) any change in percentage holding of non-performing loans across other banks;
- (18) any change in the general character or nature of business / activities, disruption of operation due to natural calamity etc. of the listed entity;
- (19) any attachment or prohibitory orders restraining the listed entity from transferring security receipts;
- (20) initiation or status update with respect to reference to National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 of any underlying assets;
- (21) intimation in advance of the meeting of its board of directors, at which the recommendation or declaration of issue of security receipts or any other matter affecting the rights or interests of holders of security receipts is proposed to be considered and also outcome of such meetings;
- (22) fraud or defaults by sponsor or key managerial personnel or arrest of key managerial personnel or sponsor;
- (23) change in directors, key managerial personnel (Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer , Company Secretary etc.), Auditor and Compliance Officer of the Sponsor;
- (24) in addition to the above, the listed entity shall provide all such disclosures to the Stock Exchange(s) as it is required to make before the Reserve Bank of India as per the extant requirement and/or any other disclosure(s) as prescribed by Reserve Bank of India from time to time;
- (25) in case where an event occurs or an information is available with the listed entity, which has not been indicated in these regulations, but which may be material, the listed entity is required to make adequate disclosures in this regard.”

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT-III/4/Exty./215/18]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 08, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29,

2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD NRO/GN/2018/13.
- i) June 01, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 08, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
